

प्रेषक,

अनूप वधावन,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
शहरी विकास विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2 :

देहरादून: दिनांक-14 सितम्बर, 2009

विषय:- एकीकृत कम लागत सफाई योजना, 2008 के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश एवं राज्यांश धनराशि के व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवर सचिव, आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या O-17024/24/2009-ILCS दिनांक 22-6-2009 के माध्यम से एकीकृत कम लागत सफाई योजना, 2008 के अन्तर्गत राज्य की 6 नगर निकायों क्रमशः हल्द्वानी, रुद्रपुर, देहरादून, मंगलौर, रुड़की एवं चमोली-गोपेश्वर हेतु कुल 1613 शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित किये जाने की डी0पी0आर0 स्वीकृत की गयी है तथा पे एण्ड एकाउंट आफिसर, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 6-7-2009 द्वारा एकीकृत कम लागत सफाई योजना, 2008 के अन्तर्गत रू० 31.00 लाख केन्द्रांश स्वीकृत किया गया है, जिसके सापेक्ष देय 15 प्रतिशत राज्यांश रू० 6.20 लाख होता है।

अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार योजनान्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश रू० 31.00 लाख तथा देय राज्यांश रू० 6.20 लाख, अर्थात् कुल रू० 37.20 लाख (रूपये सैतीस लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
2. उक्त धनराशि शहरी विकास विभाग के अनुदान संख्या-13 सामान्य बजट तथा अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जाति उपयोजना बजट से स्वीकृत की जा रही है।

3. अवर सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या O-17024/24/2009-ILCS दिनांक 22-6-2009 के क्रम में केन्द्रीय समन्वय समिति की बैठक दिनांक 26-5-2009 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा योजना की नवीनतम गाईड लाईन्स में दिये गये निर्देशों का सूडा द्वारा अनुपालन करते हुए योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।
4. राज्य समन्वय समिति की बैठक दिनांक 24-8-2009 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. योजनान्तर्गत 75 प्रतिशत केन्द्रांश, 15 प्रतिशत राज्यांश स्वीकृत किया जा रहा है। अवशेष 10 प्रतिशत लाभार्थी अंशदान भारत सरकार की गाईड लाईन तथा दिनांक 24-8-2009 को हुई राज्य समन्वय समिति की बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्राप्त किया जायेगा।
6. उक्त अनुदान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।
7. व्यय करते समय वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुवल/उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 तथा इसके क्रम में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश मितव्ययिता के विषय में शासन के आदेश एवं तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।
8. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (उत्तराखण्ड) को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य भेज दी जाय।
9. उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत करते हुए त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार व शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. अनुदान संख्या-30 के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का मासिक प्रगति रिपोर्ट, भौतिक प्रगति सहित समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ तथा शहरी विकास विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा, जो कि अनुदान संख्या-13 की प्रगति आख्या के अतिरिक्त होगा।
11. यदि किसी बिन्दु पर भारत सरकार की गाईड लाईन्स व राज्य समन्वय समिति के निर्देशों में विरोध हो तो उस दशा में भारत सरकार की गाईड लाईन्स के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।
12. उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष-2009-10 के आय-व्यय के अनुदान सं0-13, लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-02-कम लागत के व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण-20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता की मद के नामे **रु0 27.90 लाख** की धनराशि तथा **अनुदान सं0-30, लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-02-कम लागत के व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण-20 सहायक**

अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता की मद के नामे रू0 9.30 लाख की धनराशि डाला जायेगा।

13. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0- 416/XXVII(2)/2009, दिनांक 08 सितम्बर, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनूप वधावन)  
सचिव।

भा.क्ष. 203  
सं0 (1)/IV(2)-शा0वि0-09, तददिनांक।

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अवर सचिव, आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार को उनके पत्र संख्या O-17024/24/2009-ILCS दिनांक 22-6-2009 के क्रम में।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निजी सचिव, मा0 नगर विकास मंत्री जी।
5. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
- ✓ 10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)  
अनु सचिव।